SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir so far as Belgaum is concerned we will definitely consider that.

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Chairman, Sir, the problem of exodus of Indian Airlines' pilots to private operators is the creation of the Government. Firstly, the Government has allowed the private operators to operate on the scheduled routes against the law of the country. The Air Corporations Act prohibits privatisation of the airlines on the scheduled routes, yet his predecessor did not heed to our requests or suggestions and he allowed the private operators to operate on the scheduled routes. Now they have been facing the problem of exodus of pilots.

MR. CHAIRMAN: The same question has been asked earlier. Will you... *(Interruptions)* . . .

SHRI DIPEN GHOSH: My first question is whether the Government realises that it is their folly and because of that this problem has been created. Now people say that one of the private operators has connection with a certain international mafia group. That is there. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Please... *(Interruptions)* ... Please.

SHRI DIPEN GHOSH: Anyway, Mr. Chairman, Sir, my specific question is...

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, allegations of this nature are made that one of the operators is connected with a mafia group when he is not able to defend himself. *(Interruptions)* . . .

SHRI DIPEN GHOSH: What are the steps that the Government is going to take or proposes to take to prevent the exodus of pilots from Indian Airlines to private sector?

MR. CHAIRMAN: This question has already been answered by the Minister. Now I will go to Question No. 443. Question No. **443**.

*443. [The questioner (Dr. Narreddy Thulasi Reddy) was **absent**. For answer, Vide Col.....**infra.**]

वस्त्र उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिक का उपयोग

*444. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है कि देश में वस्त्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीनतम मशीनों की प्रौद्योगिकी की जरूरत है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विदेशों से पुरानी और प्रयुक्त वस्त्र उत्पादन मशीनों के आयात पर अदा किये जाने वाले सीमा शुल्क में काफी छूट प्रदान की हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस छूट के परिणा स्वरूप पुरानी मशीनों की लागत, स्वदेश में निर्मित नई मशीनों की लागत की तुलना में कम हो गई है और इस तरह देश में मशीन निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) पुराने पूंजीगत माल का आयात करने के लिए कोई पृथक शुल्क ढांचा नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, पुरानी मशीनों की लागत नई मशीनों की तुलना में हमेशा ही कम रही है।

सभा में यह प्रश्न श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पूछा गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, कई बार मंत्रियों के उत्तर सुनकर बहुत हैरानी होती है। जिस सत्य को सारा जग जानता है और सारे लोग स्वीकार करते हैं, हमारे मंत्री कई बार उस तथ्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहते।

सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने प्रश्न के भाग (ग) में यह जानना चाहा था कि "क्या यह सच है कि सीमा शुल्क की छूट के परिणामस्वरूप पुरानी मशीनों की लागत स्वदेश में निर्मित नयी मशीनों की तुलना में कम हो गयी है" और जवाब आया है, "प्रश्न ही नहीं उठता।" तथापि पुरानी मशीनों की लागत नयी मशीनों की तुलना में हमेशा ही कम रही है सभापति जी, मैंने देश की पुरानी मशीनों की लागत की तुलना नहीं की थी। मैंने विदेशों से आयात की जा रही पुरानी मशीनों की तुलना देश में बन रही नयी मशीनों की लागत से की थी। इसलिए मंत्री महोदय मानें या न मानें यह सच्चाई है कि जब आयात शुल्क घटा दिया जाएगा तो विदेशों से आयात की जा रही पुरानी मशीनों की लागत देश में बन रही नयी मशीनों की लागत में बहुत कम हो जाएगी जिससे देश में बन रहीं नयी मशीनों के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहती हूं कि जब कि सरकार यह मान रही है कि वस्त्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीनतम मशीनी तकनीक की जरूरत है तो फिर आयात शुल्क घटाकर आप भारतीय उद्योगपति को इटली और साउथ कोरिया का जंक खरीदने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे इटली की अर्थ व्यवस्था तो सुधरेगी लेकिन हमारा देश वस्त्र तकनीक में पीछे ही रहेगा। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आई० एम० एफ० के प्रेशर के तहत बनायी गयी इस नीति पर क्या सरकार पुनर्विचार करेगी?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति महोदय, ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है, 1988-89 में हमारा जो इंडीजिनस प्रोडक्शन 484.05 है और 91-92 का जो प्रोडक्शन है, जो मशीनें बनायी हैं वह 129.60 है। तो हमारे देश में इंडीजिनस प्रोडक्शन टैक्सटाइल मशीनरी का पहले से बढ़ा हुआ है, घटा नहीं है। मगर मैं ऑनरेबल मेंबर को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज देश में हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो टैक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, टोटल एक्सपोर्ट में 33 परसेंट हमारा एक्सपोर्ट है और अध्यक्ष जी, बाहर के देशों से अगर कम्पटीशन करना है और हमारे पास न्यू टैक्नोलोजी और मशीन नहीं हैं तो अध्यक्ष जी मैं ऑनरेबल मेंबर को इनफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 110 साल की मशीनरी को लेकर हम दुनिया के कम्पीटीशन में किस तरह से जा सकते हैं? दूसरी कंट्रीज की जो टैक्सटाइल मशीनरी है, बिल्कुल लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के साथ वे लोग प्रोडक्शन में आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, यही नहीं बल्कि हमारे हिन्दुस्तान के जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, जब सैकिंड हैंड मशीनरी को लाने की इजाजत नहीं थी तो वई दफा उन लोगों ने फोर्स किया कि दुनिया के मुकाबले में हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इम्पोर्ट करने की इजाजत दी जाए। तो इसलिए आज जो नई इंडस्ट्री लिब्रलाइजेशन पालिसी के तहत हमने जो लोगों को दिया है, उसमें जैसा मैंने बताया कि यह सिर्फ टैक्सटाइल में इम्पोर्ट के लिए ही नहीं हैं, यह सारी मशीनरी के साथ टैक्सटाइल सैकिंड हैंड मशीनरी को लाने की इजाजत हमने दी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मंत्री महोदय मेरा सवाल समझे ही नहीं। वह जो आंकड़ा दे रहे हैं...

MR. CHAIRMAN: Please ask your second supplementary.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं सैकिंड सप्लीमेंटरी ही पूछ रही हूं, लेकिन वह जो आंकड़ा दे रहे हैं, वह तो इस बजट से पहले का है, आयात शुल्क तो इस बजट में घटाया गया है। तो इसका

जो असर पड़ेगा वह तो आगे जो देश में निर्माण हो रही है मशीनरी, उस पर पड़ेगा। पिछले आंकड़े से तो मेरी बात साबित होती है, पर जो आप कह रहे थे कि 100 साल पुरानी मशीन से हम बात नहीं करेंगे, यह तो मैं ही कह रही हूं। मैं तो स्वयं कह रही हूं कि नवीनतम मशीनी तकनीक की जरूरत है और इसीलिए कह रहीं हूं कि जो देश में नई मशीनरी बन रही है उसको प्रोत्साहित कीजिए, विदेशों से पुरानी मशीन लाने को प्रोत्साहन मत दीजिए। वह सवाल समझे ही नहीं।

चलिए, अब आप दूसरा सप्लीमेंटरी कह रहे हैं तो मैं दूसरा सप्लीमेंटरी यह जानना चाह रही हूं कि मंत्री महोदय को यह पता होगा कि 1986 में आपके मंत्रालय में एक वस्त्र उद्योग में आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई थी, जिसके तहत 1,357.3 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था जिसमें से करीब 800 करोड़ रुपया आबंटित भी किया गया, तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि 1986 से चल रही इस योजना का कोई मूल्यांकन आपने किया है कि हमने वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण में कितना लक्ष्य प्राप्त किया है, कितनी सफलता प्राप्त की है?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, 750 करोड़ रुपया आई.डी.बी.आई. में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जमा किया है जो मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत उस रकम को लेकर मॉडर्नाइजेशन टैक्सट इल इंडस्ट्री में करे और प्रोडक्शन को यह इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया का उद्देश्य था, जिसके तहत 750 करोड़ रुपए के बजाए 850 करोड़ रुपया प्राइवेट सैक्टर में भी और एन.टी.सी. में भी इस्तेमाल किया गया है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है और उसके तहत प्रोडक्शन आगे बढ़ रहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मूल्यांकन किया है क्या? ये तथ्य तो मैंने ही दिए आपको, जो आपने तथ्य दिए, वे तो मैंने खुद ही दिए थे आपको कि इतना रुपया स्वीकृत हुआ, इतना आबंटित हुआ। कोई मूल्यांकन किया होगा कि आपको इस बारे में कितनी सफलता मिली है? कोई इवेलूएशन किया है क्या उसका?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, मैंने कहा कि रेनोवेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है और प्रोडक्शन आगे बढ़ा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह तो रस्मी जवाब है अध्यक्ष जी, मैं तो स्पेसिफिक जवाब चाह रही थी। यह तो कोई कह देगा कि प्रोडक्शन बढ़ा है। किस एजेंसी ने इवेलूएशन किया, कितना लक्ष्य हासिल हुआ? कोई स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। अब इस तरह के रस्मी जवाबों से हमारी संतुष्टि नहीं होती।

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, वह जवाब किस तरह का चाहती हैं, वे अगर ऑनरेबल मेम्बर बताएं तो मैं स्पेसिफिक जवाब भी देने के लिए तैयार हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं यह जानना चाहती हूं कि किस एजेंसी ने एवेलूएशन किया? उस समय कितना प्रोडक्शन था, जब इवेलूएशन नहीं हुआ था? 850 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ? यह स्पेसिफिक आंकड़े चाहिएं और किस एजेंसी के द्वारा हुआ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं ऑनरेबल मैम्बर को स्पेसिफिक जवाब लिखकर भेज दूंगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : शुक्रिया आपका।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, I will ask of the hon. Minister a very simple question. It is a coincidence that the hon. Finance Minister is sitting very close to him. If he has no answer, he can take the help of the Finance Minister. Sir, th

Government has provided a lot of support to the mill sector by lowering the customs duty. Sir, the mill sector uses imported raw material and its exports are very low. The handloom sector uses indigenous raw material but its exports are very high. I would like to know why the Government is giving so much of support to the mill sector and not to the handloom sector?

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, इसमें अभी हम हैंडलूम सेक्टर की तरफ तरक्की के लिये जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आनरेबल मेंबर को यह गलतफहमी है कि हम मिल सेक्टर को ही कर रहे हैं। आज मिल सेक्टर बहुत खराब हालत में दिन पर दिन आती जा रही है, मैं आनरेबल मेंबर के इंफामशन में ला रहा हूं। प्रोडक्शन की जो केपेसिटी है सबसे ज्यादा पावरलूम की है, सेकेंड आता है हैंडलूम और मिल सेक्टर में प्रोडक्शन आज आखिर में आ गया है। तो मैं उसके आकड़े भी आपको देने के लिये तैयार हूं, क्योंकि हैंडलूम सेक्टर में जो यूज हो रहा है उसमें भी फाईबर यार्न को यूज किया जा रहा है। मैं आनारेबल मेंबर को यह इंफार्मेशन देना चाहता हूं कि हैंडलूम सेक्टर का एक्सपोर्ट तकरीबन 11 सौ करोड़ है और आज मिल सेक्टर का बहुत ज्यादा है—हजारों करोड़ों में।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो सिक मिलें हैं टक्सटाईल की, क्या उसका यही कारण है कि उनकी जो मशीनरी है बहुत ओल्ड ऐज हो गई है और वह इकानामिकली फिजिबिल नहीं है तथा वह आउट-डेटिड मशीनरी है। जहां तक मेरी जानकारी में है, मेरे नान्दयाल डिस्ट्रिक्ट में एक एन० टी०सी० मिल है जो बहुत अच्छे प्रोफिट में चल रही थी, मगर ओल्ड ऐज मशीनरी होने की वजह से दो-तीन साल से वह बीमार उद्योग हो गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी बीमार मिलें – सिक मिल्स हमारे देश में कितनी हैं? सरकार के पास क्या व्यवस्था है कि इन सिक मिलों को मौडर्न टैक्नोलोजी में इंटरोड्यूज करके इनको फिर से चलाया जाए? हमारे शहर की जो एन०टी०सी० मिल है उसका एक प्लान भी सरकार को दिया गया है कि कितना पैसा लगता है उसके न्यू टेक्नोलोजी और न्यू मशीनरी के लिये। तो सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है इस प्लान को स्वीकार करने में?

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी एन०टी०सी० मिल नान्दयाल में हैं और इस तरह की देश में 124 मिल्स हैं, जो एन०टी०सी० चला रही हैं जिसमें नान्दयाल मिल भी एक है। मगर जैसा आनारेबल मेंबर जानना चाहते हैं, यह निजाम के समय की है, क्योंकि मैं भी उसी स्टेट से आता हू वह 60 साल पुरानी मशीन को लेकर अब तक चलते, गिरते, पड़ते यहां तक आये हैं और उसके माडर्नाइजेशन के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने केबिनेट में डिसीजन लिया है 533 करोड़ रुपये का टोटल एन०टी०सी० टैक्सटाईल इंडस्ट्री के माडर्नाइजेशन के लिये। इसमें 89 करोड़ रुपये इक्विटी दिया है और बाकी रकम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर हिन्दुस्तान के जितनी भी एन०टी०सी० की जो सिक मिलें हैं उनका माडर्नाइजेशन के लिये प्लान तैयार हुआ है और वह आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को आई०डी०बी०आई० – फाइ-नेंशियल इंस्टीट्यूशन से रकम लेकर माडर्नाइजेशन करने का हम आपको आश्वासन देते हैं।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : कब तक पूरा किया जायेगा, कोई टाईम लिमिट है इसके लिये? क्योंकि 8–10 हजार कामगार हमारे डिस्ट्रिक्ट में बेकार हो गये हैं।

श्री जी० वेंकटस्वामी : अभी शुरू ही नहीं हुआ तो कब तक पूरा होगा,

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आपका कोई प्रोग्राम तैयार हुआ हो उसके बारे में ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : जब शुरू होगा तो मैं डेट बतला सकता हूं।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप कब शुरू करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)** सर बहुत इंपोर्टेंट हैं। हमारे दस हजार परिवार आज बेकार पड़े हैं।

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Hon. Chairman, Sir, we see two types of machinery are coming into this country. One is, new machinery and the second is unused but not new.

That is how the importers, or people of other countries are exporting the machinery with zero customs duty. They are coming in competition with the indigenous machinery. Therefore, will the Government consider increasing or putting customs duty on the import of textile machinery coming into the country?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, मि० कोटैया हैंडलूम से टेक्सटाईल में चले गये हैं। वह एक्सपर्ट हैं हैंडलूम में। नई बात बताई है कि नई मशीनरी को भी रखकर सेकंड हैंड मशीनरी इम्पोर्ट करते हैं। यह इंफार्मेशन वह दे रहे हैं। अध्यक्ष जी अगर मेंबर के पास यह सीक्रेट है तो जरा हमको भी बतला दें ताकि हम उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकें।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the problem of NTC mills started much earlier and the successive Governments and successive Ministers only delayed the whole thing. And, in the meantime, the situation has become very acute. Therefore, Sir, it is not only a question of giving a promise for modernisation but the time-frame that is very important. And, in the meantime, Sir, perhaps the Minister knows, electric supply, water and all that have been discontinued to a number of textile mills in Kanpur. So, the production has virtually stopped and there is idle-wage payment. Therefore, Sir, in view of this urgency, will the Minister convey to the House his willingness to execute a plan to modernise it at a very early date so that the mills do not become further sick and the situation does not become irretrievable?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, देश में मैंने जिस तरह से बताया कि जितनी भी सिक मिल्स हैं वह एन.टी.सी. का खजाना बन गई हैं। एक लाख साठ हजार वर्कर्स आज इनमें हैं। अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी डिसीजन लिया है कि इन लोगों के माडर्नाइजेशन के बगैर ये इंडस्ट्रीज जिंदा नहीं रह सकतीं और ये सारे वर्किंग क्लास के लिये जो भी हमें मदद करनी है, वह करने का भी डिसीजन लिया है। मगर आनरेबल मेंबर ये जानते हैं कि मैंने जिस तरह से इससे पहले भी जवाब दिया कि माडर्नाइजेशन के रास्ते को हमने अख्तियार किया है और उस रास्ते को अख्तियार करके हम आगे बढ़ेंगे। मगर मैं आनरेबल मेंबर से ये कहना चाहता हूं कि आईडिल वेज आज कई सालों से दिया जा रहा है। ये हमारे कंट्री का जो बजट है आर्गेनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिये नहीं है बल्कि अन-आर्गेनाईज्ड वर्किंग क्लास, which constitutes 70 per cent of the population of this country. उन लोगों को दे रहे हैं ये टैक्स। तो उनके लिये हमने क्या आर्गेनाईज किया है, क्या मदद कर रहे हैं, मैं आनरेबल मेंबर को बताना चाहता हूं। तो उनका भी हमें ख्याल करना चाहिये। उनका पैसा लाकर आर्गेनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिये कितने साल आईडिल वेज देंगे ये ? इसके लिये माडर्नाइजेशन करने के लिये जा रहे हैं **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, for this, the Government has to

be blamed because it has delayed the modernisation for decades. Therefore, instead of directing the question to me, you kindly attend to the problem. I want you to specify as to how long you will take to modernise it instead of giving sermons on the reasons of delay for the idle-wage payment.

SHRI V. NARAYANASAMY: The hooligans are not cooperating for modernisation. You should know that also.

*445. [The questioner (Chaudhary Harmohan Singh) was absent. For answer, vide col...infra.]

Import of feature films by doordarshan

*446. SHRI RAJESHWAR RAO: †
DR. SHRIKANT RAMA-CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the number of feature and short films that were imported during the last three years and from which countries;

(b) what was its total value.

(c) what has been done about these films after their import; and

(d) what is Government's present policy about such imports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri V. Rajeshwar Rao.

Statement

(a) and (b) During the period 1989 to 1992, Doordarshan obtained the telecast rights of 24 feature and short films from United Kingdom, Singapore, France and Spain for an amount of US$ 114,600.

(c) 19 of the 24 films have already been telecast by Doordarshan. The remaining 5 will be telecast depending upon its programme requirements.

(d) According to the current export import policy Doordarshan can import cinematographic feature films and video films without a licence provided it obtains from the administrative officer, Central Board of film Certification or any other officer designated for the propose by the Ministry of Information and Broadcasting the certificate to the effect that the film has:—

(i) won an award in any of the International Film Festivals notified by the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India; or

(ii) participated in any of the official sections of the notified International Film Festivals; or

(iii) received good reviews in prestigious film journals notified by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

SHRI V. RAJESHWAR RAO: Sir, he has not replied to what I have asked. Now, I want to know from the hon. Minister as to what the mechanism is by which the films are selected. This is my first supplementary.

SHRI K. P. SINGH DEO: Could you kindly repeat?

MR. CHAIRMAN: What is the mechanism by which the films are selected?